an>

Title: Statement regarding Government Business for the week commencing 20th April, 2017.

माननीय अध्यक्ष : आयटम नम्बर, 17, श्री अनंत कुमार जी।

â€¦(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, ... *

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्री एस.एस. अहलुवालिया जी की ओर से यह सूचित करता हूं कि सोमवार 20 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाये। ...(व्यवधान)

(एक) आज की कार्य सूची, (जिसमें रक्षा, गृह और कोयला मंत्रालय के लिए वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान करना शामिल हैं) से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।..(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदया,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें क्या है?

â€¦(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : (दो) वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे(सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(तीन) संबधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

(चार) वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बजट के संबंध में बकाया अनुदान मांगों का गिलोटिन।

(पांच) विनियोग विधेयक, 2017 का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not allowing you. What is this? Nothing will go on record. I have not allowed him.

*â€¦(Interruptions)â€¦ **

श्री अनन्तकुमार : (छः) वित विधेयक, 2017 पर विचार और पारित करना।

(सात) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान -

(क) वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे (रेल)।

(ख) वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: What is this? Nothing will go on record.

â€¦(Interruptions)â€¦

श्री अनन्तकुमार : (आठ) संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय सदस्यों द्वारा सब्मिशन।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, उपस्थित नहीं। श्री पंकज चौधरी।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव को अगले सप्ताह (20.03.2017 से 24.03.2017) की कार्य सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

यह सभा आनंद नगर जंक्शन, व रास्ता महाराजगंज, घुघुली रेल मार्ग जिसका फाइनल सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। मैं इस रेल मार्ग को शीघ्र निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव करता है।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, the following item may be taken up for discussion during the next week's business.

In my constituency, Krishnagiri, the Krishnagiri Postal Division was formed after 20 years by bifurcating from Dharmapuri Division on 4.3.2011. After formation of Krishnagiri Postal Division, not even a single OA/PA was deputed to Krishnagiri Division from Dharmapuri Division. The sanctioned strength is 141 staff but it is left with only 100 staff. Since formation, there is a shortage of 40 to 50 staff. Due to shortage, the staffs are suffering much even to take short leave. Beyond the problem, relief arrangements for deputation, leave, frequent training and review at RO/CBS band with problem is causing great concern and stress to the officials.

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : महोदया, आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा करें -

1. पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना, जो कि लोकप्रिय योजना है, के तहत तीर्थ स्थलों के विकास के लिए है, सरकार कार्य कर रही है, किंतु महाराष्ट्र के नागपुर एवं वर्धा तथा अमरावती की कई योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। उन कार्यों की स्वीकृति का कार्य।

2. भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा नए राजमार्गों के दिनांक 3 जनवरी, 2017 को स्वीकृत महाराष्ट्र प्रदेश के लिए किया गया है। इस कार्य को शीघ्र करवाने हेतु धनराशि आवंटित करने का कार्य।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam, I hereby request you to include the following in the List of Business for next week of the Budget Session of the Parliament commencing on 20th Mach, 2017:

1. Day by day more number of Central Welfare Schemes is being linked to the SECC 2011 Survey. There are two major problems with this stand of the Government which may affect the development of the whole country. First, it is a known fact that there were more than 8 crore mistakes in the SECC data and around 1.46 cores were yet to be rectified until July 2015. This is coupled with the fact that a large number of households have been missed in the Survey. Secondly, many of the exclusion criteria are perverse and unfair, which therefore poses a risk of leaving out millions of people from the development process.

2. Lack of Rural Sanitary Marts on ground and even those present are not working effectively to sell construction materials for beneficiaries under SBM(G), leading to escalation of costs of toilet construction of beneficiaries.

Hence, I request these issues to be inserted in the List of Business for the next week for detailed discussion.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा करें -

1. मेरे मत क्षेत्र अमरेली के महुआ में प्याज का उत्पादन बहुत होता है। मेरा आग्रह है कि प्याज के किसानों की भलाई के लिए रेलवे के द्वारा प्याज की ढुलाई की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां के व्यापारियों को और अधिक लाभ मिल सके। परन्तु रेल यातायात के अभाव के कारण वहां के किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरी मांग है कि इन स्थानों में रेल यातायात की व्यवस्था सुगम की जाए। इससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और रेलवे को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

2. गुजरात राज्य में राजुला जाफराबाद के समुद्र में वहां के स्थानीय निवासी, जो मछली उद्योग पर ही निर्भर हैं, जब वे मछली पकड़ने के लिए अपनी बोट लेकर समुद्र में जाते हैं, तो अनेकों बार उनकी बोट बड़े-बड़े जहाजों से टकराकर नष्ट हो जाती है और मछुआरों की मौत भी हो जाती है। अतः मेरी मांग है कि समुद्र के मध्य में यदि कोस्टगार्ड की गश्त बढ़ा दी जाए, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है और साथ ही साथ मछुआरों को उनका हम और न्याय दिलाने की प्रक्रिया में मदद हो सकती है।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महोदया, आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा करें -

1. आदिवासी एवं नक्सलवादी क्षेत्र में स्थित वड़सा-गड़चिरौली रेलवे लाइन, जिसका रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है तथा फाइनल लोकेशन सर्वे एवं भू-तकनीकी सर्वे भी पूरा किया जा चुका है, को एवं नागपुर-नागभीड़ के आमान परिवर्तन, जिसका संशोधित प्राक्कलन विद्युतीकरण के साथ तैयार है, के शीघ्र निर्माण के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रकल्प पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए धन का आवंटन किए जाने से संबंधित विषय।

2. महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विभाग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 271 (1) के अंतर्गत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 29.7.2016 में एक प्रस्ताव, जिसमें 149.37 करोड़ रुपए की राशि अंतर्निहित है, प्रेषित किया था, जिसमें केंद्र सरकार ने 128.37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इनमें से 105.52 करोड़ रुपए एडहॉक बेसिस पर जारी भी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उपरोक्त योजना के तहत रिवाइज्ड प्रपोजल 6.1.2017 में पुनः प्रेषित किया है, को स्वीकृति प्रदान किए जाने से संबंधित विषय।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 27 पर कालपी नगर में राजमार्ग के अनिर्मित हिस्से को बनाने के संबंध में; और

2. बुंदेलखंड में ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद होने के कारण किसानों को हुए नुकसान पर राहत देने के संबंध में।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत द्वितीय विश्वयुद्ध एवं बंगलादेश की लड़ाई के समय सैनिकों के द्वारा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया था, इस एयरपोर्ट को विकसित किया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में टाटा स्टील, जो एक बड़ी कम्पनी है, के साथ ही आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र भी है, जिसमें हजारों की संख्या में उद्योग स्थापित हैं। सम्पूर्ण कोल्हान प्रमंडल माइंस से भरा पड़ा है, इसलिए वहाँ पर देश-विदेश से व्यवसाय एवं शिक्षा हेतु लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इससे झारखण्ड के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि जमशेदपुर से इसकी दूरी 35 किलोमीटर है। यह इस क्षेत्र के समुचित विकास हेतु अत्यंत जरूरी है।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के बोड़ाम, पटमदा, कांटिन (पश्चिम बंगाल) तथा बहरागोड़ा, घोड़ाबांधा, पोटका (ओडिशा) का सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के लोगों के मोबाइल में पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा का टावर पकड़ता है, जिसके कारण वहां के लोगों को रोमिंग का चार्ज देना पड़ता है। यह आदिवासी बहुल, गरीब, उग्रवाद प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोमिंग चार्ज कटने के कारण यहाँ के लोग मोबाइल से बात नहीं कर पाते हैं, इसिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर नये टावर लगाए जाएं, ताकि यहाँ के लोगों की परेशानी दूर हो सके।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करते हुए, उन पर चर्चा कराने की

कृपा की जाए:-

1. झारखण्ड राज्य में वर्ष 2009 से साक्षरता मिशन कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। विशेषकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत यह कार्यक्रम वर्ष 2010 से चलाया जा रहा है। साक्षरता मिशन में लगे हुए महिला एवं पुरुष को नियुक्ति पत्र तक नहीं मिला है, न ही मानदेय निर्धारित है और न ही उनको चिकित्सा सुविधा है। ड्रेस कोड भी इन लोगों को उपलब्ध नहीं है।

   अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि इन्हें कम से कम मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूर के बराबर ही मानदेय दिया ताकि वे मन लगाकर काम कर सकें।

2. झारखण्ड राज्य में कार्यरत सेविका सहायिका हैं, जो साल में 365 दिन काम करती हैं और इनकी सरकारी नौकरी की आयु सीमा भी समाप्त हो चुकी है। इन लोगों को लगभग 4000 रुपये मानदेय मिलता है। इनको न तो चिकित्सा सुविधा मिलती है और न ही इनकी ग्रेच्युटी की कटौती होती है। इनको प्रमोशन देकर इनसे सुपरवाइज़र के रूप में काम लिया जाए।

   अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों के बराबर इनको मानदेय दिया जाए।

12.18 hours

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2016-2017